pan>

Title: Regarding need to raise additional Battalions of Eco Task Force for maintenance and restoration of ecology in hill States.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : इको टास्क फोर्स, पर्यावरण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक बल है, जिसमें पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संरक्षण के साथ-साथ देश की सेवा में अपनी जवानी समर्पित करने वाले सैनिकों का सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्वास भी होता है। इस समय देश में चार इको टास्क फोर्स तैनात हैं। एक मोहनगढ़, राजस्थान में, पिथौरागढ़ व देहरादून, उत्तराखण्ड में तथा एक दहू, जम्मू-कश्मीर में स्थित हैं। इको टास्क फोर्स ने क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक जीवन पर भी अपनी छाप छोड़ी है। देहरादून स्थित बटालियन द्वारा जहां एक ओर क्षेत्रीय लोगों को पर्यावरण रक्षा हेतु प्रेरित करने का अभूतपूर्व कार्य किया है वहीं वÂ◌ाऱ 2002 से 2008 तक मसूरी रोड पर सफलतापूर्वक 18.71 लाख वृक्ष रोपित किए गए। डैम, सुरक्षा दीवारों का निर्माण करने के साथ बटालियन द्वारा क्षेत्रीय लोगों को इपधन और पशुचारा उपलब्ध कराया गया। इको टास्क फोर्स द्वारा देश में किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। जिन सैनिकों ने एक समय देश की रक्षा तोप, टैंकों और बंदूकों द्वारा की, आज वे कुदाल, फावड़ा लेकर दूसरी पारी में देश के संवेदनशील क्षेत्रों के पर्यावरण की रक्षा हेतु समर्पित हैं।

मेरा मानना है कि देश के सभी हिमालीय राज्यों की संवेदनशीलता के दÂ◌िटगत इनके लिए ईको टास्क फोर्स की अतिरिक्त बटालियनों का गठन अविलंब किया जाना चाहिए, क्योंकि दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा कोई अन्य एजेंसी इतनी सक्षमता एवं कार्यकुशलता से नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त, इसके द्वारा हमारे भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानजनक रोज़गार मिल सकेगा।

मैं सरकार से पुरज़ोर आग्रह करता हूं कि पारदर्शिता, जवाबदेही, निगरानी तंत्र को ज्यादा सार्थक बनाते हुए वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और इसके लिए सेवानिवृत्त वन अधिकारियों की सेवाएं ली जा सकती है। सेना के अधिकारी दो-तीन साल के लिए प्रोजेक्ट में कार्य करने आते हैं। जबकि मेरा मानना है कि उसकी सफलता के लिए उनका प्रोजेक्ट की पूरी अवधि तक रहना आवश्यक है। स्थानीय नागरिकों, वन पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं से ज्यादा समन्वय की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि क्षेत्र के समन्वित विकास की अवधारणा को धरातल पर लाया जा सके।